

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या:— 31/2022

1. बाबूलाल आयु 48 वर्ष पुत्र हनुमानाराम
2. विक्रम कुमार आयु 38 वर्ष पुत्र हनुमानाराम
3. राकेश आयु 23 वर्ष पुत्र दलीप सिंह

समस्त जातियान मेघवाल, निवासीगण तोखा का बास, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
— अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।

— रेस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 789 दिनांक 06.01.2022 जो तहसीलदार सूरजगढ द्वारा पारित किया गया।

उपस्थित:—

1. श्री हजारी लाल सूनिया, अभिभाषक — अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक — रेस्पोजेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 03.08.2022

उक्त विषयक अपील मय प्रार्थना पत्र स्थान, प्रा0प0 अ0धा0 96 जा0दी0 एवं प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 के विद्वान तहसीलदार सूरजगढ के नामान्तरकरण संख्या 789 दिनांक 06.01.2022 भूमि ग्राम तोखा का बास के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र अ0धा0 96 जा0दी0 एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र अ0धा0 96 जा0दी0 एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किये जाते हैं। अपील अपीलान्त के अनुसार मौजा ग्राम तोखा का बास मे भूमि खसरा नम्बर 224 रकबा 0.06 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 225 रकबा 2.39 हैक्टेयर अवस्थित है। उक्त भूमि ग्राम पंचायत भगीना के ग्राम तोखा का बास की आबादी से लगती सार्वजनिक भूमि है जो राजकीय विघालय तोखा का बास की है तथा उक्त भूमि मे सार्वजनिक कुआं बना हुआ है तथा उक्त भूमि रियासतकाल से ही सार्वजनिक भूमि रही है व ग्रामवासियों के काम मे आती रही है। उक्त भूमि ठिकाना डूण्डलोद के ठाकुर श्री हरनाथ सिंह ने सेठ हरनारायण दास ईश्वरदास काजडिया को सार्वजनिक हित एवं पुण्यार्थ कार्य करने के लिए दी थी तथा कुछ समय बाद सेठ हरनारायण दास ईश्वरदास काजडिया के वारिसान ट्रस्टी सेठ लखी प्रसाद काजडिया ने उपरोक्त भूमि लिखित मे राजकीय विघालय तोख का बास को दान कर दी थी जिसकी देखरेख ग्राम विकास सेवा समिति तोखा का बास कर रही है तथा उक्त भूमि मे अपीलान्त का हित निहित है। उक्त भूमि को हडपने के आशय से भू-माफियाओं द्वारा अपने हक मे रजिस्ट्री करवाया गया जिसके आधार पर रेस्पोजेन्ट द्वारा उक्त भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोजेन्ट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 789 दिनांकित 06.01.2022 को मनोज कुमार पुत्र बनारसी लाल, निवासी ग्राम लीखवा जिला झुंझुनूं के नाम दर्ज किया गया जिससे व्यथित होकर उक्त अपील श्रीमान् के समक्ष निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजों व खिलाफ कानून होने के कारण दर्ज नामान्तरकरण संख्या 789 मौजा ग्राम तोखा का बास दिनांकित 06.01.2022 निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 135 (2) राजस्थान भू-राजस्व

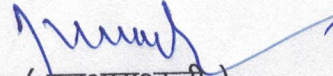
अधिनियम 1956 की पालना मौके पर जाकर नहीं की तथा सम्पत्ति का मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन किये बिना ही अपने कार्यालय में बैठे-बैठे ही अपने कर्तव्य की इतिश्री कर उक्त नामान्तरकरण संख्या 789 रजिस्ट्री के आधार पर दर्ज किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.06.2022 को जो नामान्तरकरण संख्या 789 दर्ज किया वह कानून को ताक में रखकर गलत तरीके से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये नामान्तरकरण दर्ज किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कब्जे की जानकारी किए ही नामान्तरकरण संख्या 789 दर्ज किया है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 789 विक्रय पत्र दिनांकित 10.04.2013 के आधार पर दिनांक 06.01.2022 को करीब 9 वर्ष बाद दर्ज किया है जिससे भी जाहिर हो रहा है कि नामान्तरकरण बिना जांच के दर्ज किया है। उक्त विवादित भूमि पर विक्रय पत्र में उल्लेखित क्रेता का कब्जा नहीं है तथा कब्जे के अभाव में नामान्तरकरण दर्ज किया गया है। उक्त नामान्तरकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत ग्राम तोखा का बास के नागरिक व अपीलान्ट को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिये बिना दर्ज किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज नामान्तरकरण संख्या 789 दिनांकित 06.01.2022 वाके ग्राम तोखा का बास निरस्त किये जाने के आदेश फरमावें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजों व कानून के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 135 (2) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की पालना मौके पर जाकर नहीं की तथा सम्पत्ति का मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन किये बिना ही अपने कार्यालय में बैठे-बैठे ही अपने कर्तव्य की इतिश्री कर उक्त नामान्तरकरण संख्या 789 रजिस्ट्री के आधार पर दर्ज किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.06.2022 को जो नामान्तरकरण संख्या 789 दर्ज किया वह कानून को ताक में रखकर गलत तरीके से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये नामान्तरकरण दर्ज किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कब्जे की जानकारी किए ही नामान्तरकरण संख्या 789 दर्ज किया है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 789 विक्रय पत्र दिनांकित 10.04.2013 के आधार पर दिनांक 06.01.2022 को करीब 9 वर्ष बाद दर्ज किया है जिससे भी जाहिर हो रहा है कि नामान्तरकरण बिना जांच के दर्ज किया है। उक्त विवादित भूमि पर विक्रय पत्र में उल्लेखित क्रेता का कब्जा नहीं है तथा कब्जे के अभाव में नामान्तरकरण दर्ज किया गया है। उक्त नामान्तरकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत ग्राम तोखा का बास के नागरिक व अपीलान्ट को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिये बिना दर्ज किया गया है। उक्त भूमि का ठिकाना पट्टा बना हुआ है। विवादित भूमि सार्वजनिक हित की भूमि है। उक्त भूमि में कुआ बना हुआ है। उक्त भूमि पूर्व में खातेदार रहे काश्तकारों ने स्कूल को दान में दी है। इस संबंध में एक इकरारनामा भी दिनांक 16.08.1982 को तस्दीक हुआ है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज नामान्तरकरण संख्या 789 दिनांकित 06.01.2022 वाके ग्राम तोखा का बास निरस्त किये जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने अपनी बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम तोखा का बास के कम में भरा गया नामान्तरकरण संख्या 789 दिनांकित 06.01.2022 का बेचान होने पर नियमानुसार नामान्तरकरण विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकार किया गया है। विवादित भूमि के संबंध में किसी न्यायालय का स्थगन भी नहीं था। अदालत मातहत द्वारा भरा गया नामान्तरकरण बाद जांच नियमानुसार भरा गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम तोखा का बास स्थित भूमि ख0न0 224 रकबा 0.06 हैक्टर एवं ख0न0 224 रकबा 2.45 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.45 हैक्टर का बेचान होने पर नियमानुसार नामान्तरकरण सं0 789 दिनांक 01.06.2022 विक्रय पत्र के आधार पर बाद जांच स्वीकार किया गया है। जमाबन्दी के अनुसार बेचान की गई भूमि सरकारी व सार्वजनिक नहीं है। भूमि दान के संबंध में दान पत्र एवं इकरारनामा भी विधिवत् नहीं है। अपीलान्त विवादित भूमि के कम्प में अपीलान्त यह सिद्ध नहीं कर पाया कि उसका हित इस भूमि में किस प्रकार निहित है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त की यह अपील सारहीन है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। अपील खारिज होने की स्थिति में प्रार्थना पत्र स्थगन पर अलग से सुना जाना आवश्यक नहीं है। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 03.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, मुझुनू